compensation should be given, not what happened, what didn't happen. Mr. Gurupadaswamy, please confine your self to the compensation.

SHRI M. VINCENT: We demand... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not permit; what you say will not go on record. Please sit down. I have to run this House in a proper order.

SHRI M. VINCENT: He is speaking against...

THE DEPUTY CHAIRMAN; Let him speak. Please don't interrupt.

CHRI M. S. GURUPADASWAMY: Some assessment has already been made about damage caused in Kar-nataka; compensation has been given by the Government of Karnataka. Many properties which were looted are being returned. If more compensation is necessary, that should also be given. I am a party to that. It should be given.

SHRI V. NARAYANASAMY: Ade. quate compensation was not given.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY; It should be given. I agree with you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr Gurupadaswamy, please conclude. I have got 11 Special Mentions.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Therefore, I appeal to all the Tami. Mans who have gone out of Karnataka to come back and settle down there. It is our duty, it is the duty of the Government of Karnataka, to give them security, protection. *(Interruption)* . Mr. Ramachandran, please, let me speak. Likewise, the same thing should apply to the Government of Tamil Nadu also.

Madam, that Government of Karnataka has constituted a Commission of Inquiry. They demanded a Commission of Inquiry. A Commission of Inquiry has been constituted. I think, within a short time, the Commission of Inquiry will submit its report . After the Commission of Inquiry submits its report, the Government of Karnataka will consider that report and suitable action appropriate action, will be tken on that. But I would submit...

THE DEPUTY CHAIRMAN. Dr. Bapu Kaldate.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: But I would submit that the Cauvery water dispute has got to be settled amicably, through negotiations, only. It cannot be settled by raising a dispute on the issue. It has got to be settled by negotiations, by talks. I appreciate...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Bapul Kaldate.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I appreciate the efforts made by the Prime Minister in this regard. The Prime Minister should continue the efforts and bring about a settlement of the dispuate amicably, through negotiations.

Reported move to privatise Air India and Indian Airlines

डॉ० बापू काल्दाते (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, सरकार की नीति में एक बुनियादी परिवर्तन आज नज़र आ रहा है । हमको जहां तक याद है पहली पंच वर्षीय योजना की बात जब इस देश में 1952 में चली तब यह कहा गया, जो कि उचित था, कि सार्वजनिक उपक्रोम भारत की अर्थ-व्यवस्था के केन्द्र-बिन्दु बनने चाहिए ।

Public sector ist he pivot, at the commanding heights, of the economy of

लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सरकार की नीति में यह परिवर्तन आ गया है और सरकार इस नतीजे पर आ गई है कि...

श्री अरविन्द गणेश गुलकर्णी (महाराष्ट्र): परिवर्तन हो गया है । समाजवाद ही सब खत्म हो गया है ।...

डॉ० बापू कालदाते : मैं वही निवेदन कर रहा हू । आप परेशान क्यों हैं । आपको वहीं पर आना पड़ेगा । समाजवाद जिन्दा रहेगा, आप इसकी चिन्ता मत करिए । इन लोगों की धारणाबन चुकी है कि निजी उद्योग को भारत की अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु बनना चाहिए । अगर बनना चाहिए तो साफ कहिए । हम आपका विरोध करेंगे । लेकिन छिपाकर, चोरी-छिपे जो आप कर रहे हैं, इससे हमें आशंका होती है ।

महोदया, एक कमेटी बनाई गई थी जो सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा क्यों हो रहा है उसको देखे । लेकिन घाटा क्यों हो रहा है, घाटे की व्यवस्था करना अलग बात है । मगर घाटा हो रहा है इसके लिए निजी उद्योग के हाथों में उनको देना है यह कोई तर्कसगत बात नहीं है । अब मुझे लग रहा है कि यातायात की जो सारी व्यवस्था है वह भी निजीकरण के रास्ते पर आप ले जा रहे हैं । मारुती उद्योग को आपने पब्लिक एंटरप्राइज़ करने के लिए प्रस्ताव किया था । अब आपकी नीति बदल गई है कि मारुती उद्योग को निजी उद्योग में डाल दिया गया है ।. . .

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : ज़माना बदल गया है ।
All the world is changing.

डॉ० बापू कालदाते : ज़माना नहीं बदल गया है, आप बदल गए हैं । दुनियां में क्या बदल रहा है यह हम जानते हैं ।

उपसभापति : मिस्टर कालदाते आपका हवाई जहाज कहां उतर रहा है ?

. . . *Let* it land at the proper piace.

SHRl S. JAIPAL. REDDY (Andhra Pradesh): Madam, Dr. Bapu Kaldate's aircraft is still flying.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It should not crashland. His Special Mention is about Air India and Indian Airlines. He has not reached that.

THE MINISTER OF HUMAN' RE. SOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Madam, his aircraft can fly without fuel also.

DR. BAPU KALDATE. He is giving me 'fuel'.

THE DEPUTY CHAIRMAN; You are gliding.

डॉ० बापू कालदाते : इन्हीं का ईंधन है जिसके कारण यह चल रहा है । मेरा इतना ही सुझाव है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइस भी घाटे में चल रहा । है, उसके लिए जानकारी ली जा रही है मारुती उद्योग प्राइवेटाइजेशन में गया । कल रेल मंत्रालय का प्रस्ताव हमारेस ामने आया था कि हम धीरे धीरे कैटरिंग को निकाल देंगे ।

"ओन यूअर ओन वैगन" मीन्स वैगन्स भी किसी के हवाले कर देंगे । यही एयर लाइन्स में आ रहा है । औरंगाबाद में कांटी-नेन्टल नाम की कोई एक एयर कम्पनी है उसके हवाई जहाज वहां लाने का प्रयास चल रहा है । धीरे-धीरे सारी प्राइवेट कम्पनीज को आप यहां इजाजत दें और जो घाटा हमारे सार्वजनिक उपक्रम का है वह बढ़ रहा है वह दिखाकर उनको इजाजत देने का प्रयास करें यह मुझे अच्छा नहीं लगता । मेरी सीधी मांग है कि यह सरकार एक कम्परीहैंसिव पालिसी लेकर यहां आये और कहे कि हम इन उद्योगों को सार्वजनिक उपक्रमों से हटाना चाहते हैं । यह बहाना मत बनाइये ।. . .

श्री एम० वे:० पी० साल्वे महाराष्ट्र): मैं समझा नहीं । हिन्दी में कहें तो अच्छा है कि कम्परीहैंसिव के क्या माने होते हैं ।

डा० बापू कालदाते: ऐसा है आपने एक कमेटी अपाएट की । मैं बोलता हू आपको कि कम्परीहैंसिव के क्या माने हैं । आप नहीं समझे यह मेरी दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है । यह कोई रेल में नहीं चल रहा है । यह अलग-अलग उद्योगों में चल रहा है । सरकार का काम है सरकार हमारे सामने आये और एक बार यह कह दे कि हिन्दुस्तान के सारे सार्वजनिक उपक्रम निकम्मे बन गये हैं । जैसे यहां बिरला, टाटा उद्योग समूह को देते आये वैसे अब यू ०स०ए०, कनाड़ा की जो कुछ कम्पनियां हैं उनको चलाने के लिए ना चाहते हैं क्योंकि

हमारे देश का जो बुनियादी सिद्धांत बन रहा है कि निजीकरण इज द साल्वेशन फार आल अवर इकोनोमिक प्रोब्लम्स । मैं इस धोखे की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि यह गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं । बजाय हमारे इन सारे उपक्रमों के जिनके जरिये हम देश की सही व्यवस्था कर सकते हैं और सही मदद कर सकते हैं उनको हटाना और फायदे के लिहाज से उपक्रम चलाना विदेशी कम्पनियों के हाथ में अगर दें तो सार्वजनिक हित की तरफ उपेक्षा होने की संभावना को टालने के लिए एक तो सरकार को ठीक ढंग से कदम उठाना चाहिए या अगर सरकार उसी रास्ते पर जाना चाहती है तो सरकार जो करना चाहती है वह साफ-साफ हम को बता दे । धन्यवाद ।

Harassment of the 1984 Riot victims by Nationalised Banks

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Madam, Deputy Chairman, I would like to draw the attention of this august House to the victims of November 1984 killings. After a great deal of effort it was decided that those people who have suffered a tremendous amount of loss would be given loans. The previous loan taken by them had also to be paid with interest. Now they have two loans to pay. Most of them found it impossible to' pay back both the loans including interest. Therefore, on their request it was said that the Reserve Bank would go into the matter and decide what should be done. The Reserve Bank issued instructions to other banks to please go into each case; and see for yourself in which way you can help. Unfortunately, that advice has been put into practice by *ad hoc* system. Some banks have been more generous the others, and today we And that certain bank managers have been extremely tough, they have started cases in the court and they are trying to attach the property of those who have failed to pay back the loans and the interest. On further representation, the Government has decided to constitute a committee to decide on the modalities, how these loans can be paid and what assistance can be given to thise people who had borrowed the loan.

There are a number of banks which have started court cases -for forceable recovery which is going to ruin a large number of people. So, I request the Government, through you Madam, that they should issue instructions that all such cases would be halted for the time being till the Committee has given its report and the Government has issued instructions based on that report. Until then the cases should not be proceeded with or withdrawn, if necessary.

Need to expedite construction of Houses financed by LIC in Jodh-pur under Public Housing Scheme

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आवास संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारतवर्ष में हर कौने में झौपड़ी से लेकर महल तक जन आन्दोलन से कांग्रेस पार्टी बनी और यह मुद्दा उठाती रही कि रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक को उपलब्ध कराया जाय। हमारी प्रिय नेता इन्दिरा गांधी जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया और आवास योजनायें शुरू की और हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी जी ने उनको आगे बढ़ाया और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी भी इस बजट के माध्यम से मुझे दीखता है कि उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। परन्तु खेद का विषय यह है कि हमारे प्रान्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिलकुल आंखें मुंदे बैठी है और जो योजनायें पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े नगर जोधपुर में थी और जो बड़ी महत्ती योजना थी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 40 करोड़ की राशि अलग रख करके दो हजार मकानों की एक प्रोजेक्ट सामने रखी गई थी। इसके लिए राशि अलग रख दी गई थी। उसके संबंध में राजस्थान सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है।